(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को संगणकों के बारे में विस्तृत जानकारी व उनके प्रयोग तथा 'हैंड-आन' अनुभव एवं संगणक ज्ञान को सरल बनाने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 1984–85 में संगणक साक्षरता तथा स्कूलों में अध्ययन (क्लास) के लिए मार्ग-दर्शी परियोजना शुरु की गई। परियोजना को 1991–92 तक वर्ष दर वर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जाता रहा। इस परियोजना के अन्तर्गत 1984–85 से 1989–90 तक कुल 2598 माध्यमिक/उच्चतर माध्य-मिक स्कूलों को शामिल किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 1990–91 से किसी नए स्कूल का चयन नहीं किया गया है। यह परियोजना अन्तरिक्ष अनु-प्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा 1986 में मूल्यांकित की गई। अध्ययन से अन्य बातों के साथ यह भी ज्ञात हुआ कि क्लास परियोजना के लिए छात्रों तथा शिक्षकों में अद्भुत उत्साह था। इस परियोजना को अक्तूबर, 1986 में सरकार द्वारा गठित एक कार्यदल द्वारा भी समीक्षा की गई। कार्यदल का विचार था कि परियोजना ने भारत में स्कूलों में शिक्षा के उन्नयन तथा उसे अद्यतन बनाने में अच्छी शुरुआत की है तथा इसमें शिक्षकों तथा विद्या-र्थियों में नवाचार, विश्लेषणात्मक योग्यता तथा रचनात्मकता का संवर्द्धन करने तथा प्रोत्सा-हन देने का सामर्थ्य है। कार्यदल ने सिफा-रिश की कि परियोजना को चालू रखा जाए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट-केन्द्रीय सरकार का 1991 की संख्या 11 में परियोजना के कार्यान्वयन में अनेक खामियों का उल्लेख किया, जो सरकार द्वारा 14 सितम्बर, 1991 को पहले ही संसद के पटल पर रखी जा चुकी है। रिपोर्ट में उल्लिखित खामियों को उपचारी उपायों के लिए रा० शै० अनु० प्र० परिषद्, इलैक्ट्रानिकी विभाग, परि-योजना मंत्रालय तथा कम्प्यूटर मेनटेनैंस कार्पोरेशन (सी० एम० सी०) लिमिटेड के ध्यान में लाया जा चुका है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए संगणक साक्षरता को और अधिक अर्थपूर्ण तथा कार्यात्मक बनाने के लिए परियोजना की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान एक प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या संगणक शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त निजी क्षेत्र की एजेंसियों को शामिल करके एक एकीकृत अन्तर्निवेश-वितरण प्रणाली की स्थापना, परियोजना के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इस मामले की जांच की जा रही है।

Teaching of Sanskrit in various disciplines

4161. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:

SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state whether Government propose to introduce the teaching of Sanskrit in Colleges and Universities in such courses as Philosophy, History, Archaeology, Indology, Linguistics, Architecture, Political Science, Sociology, Mathematics, etc., in which India have made significant constribution?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Government or University Grants Commission do not prescribe courses of study in Universities and Colleges. Universities are autonomous bodies and prescribe their own courses of study. The courses offered in Universities and colleges vary from University to University. In many Universities Sanskrit Language is also one of the elective subjects for combination with other specified subjects.